



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती पर अमर जवान ज्योति स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर आयोजित समारोह में कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी उनके साथ मौजूद रहे।

## ‘मैं राजस्थान के वीर शहीदों की वीरांगनाओं को प्रणाम करता हूँ’

कारगिल विजय दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने शहीदों की वीरांगनाओं को सम्मानित किया

जयपुर, 26 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को अमर जवान ज्योति शहीद स्मारक पर आयोजित कारगिल विजय दिवस के रजत जयन्ती समारोह में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले जाबाज सैनिकों को पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विषम परिस्थितियों में सीमा पर मुस्लीमों के साथ मोर्चा सम्भालने वाले हमारे शूरवीरों की बहादुरी और अदम्य साहस अतुलनीय है। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले

मुख्यमंत्री ने अमर जवान ज्योति पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनाजी, सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह आनन्द कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 61 सबरिग्या मेजर जनरल आर एस गोदारा सहित भारतीय सेना के उच्चाधिकारी, सैनिक, शहीदों के परिजन एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

एसे वीरों को मैं नमन करता हूँ। शर्मा ने कहा कि कारगिल के युद्ध में शहीद होने वाले राजस्थान के वीर शहीदों की वीरांगनाओं को भी मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने देश के लिए समर्पण की भावना

दिखाते हुए सर्वोच्च त्याग की मिसाल पेश की।

समारोह में मुख्यमंत्री ने शहीदों की वीरांगनाओं का शाल ओढ़ाकर एवं श्रीफल देकर सम्मान किया। इस अवसर

पर कारगिल युद्ध में साहस का परिचय देने वाले वीर सैनिकों को भी सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनाजी, सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह आनन्द कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 61 सबरिग्या मेजर जनरल आर एस गोदारा सहित भारतीय सेना के उच्चाधिकारी, सैनिक, शहीदों के परिजन एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

### गलता पीठ प्रकरण में यथास्थिति ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) एकलपीठ ने संपत्ति के खुर्द-बुर्द होने के आरोप की सुनवाई करते हुए मठ के महंत की नियुक्ति करने की व्यवस्था पर ही फैसला दे दिया है, जबकि एकलपीठ ने अपने फैसले में भी माना है कि रामोदराचार्य की मृत्यु के बाद उनका महंत पद समाप्त हो गया।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि एक मई 1943 को जयपुर स्टेट के हाईकोर्ट ने इन संपत्तियों को मूल के स्वामित्व में नहीं मानकर महंत के स्वामित्व में माना था। इसका विरोध करते हुए हिंदू विकास समिति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर.बी. माथुर ने कहा कि जयपुर स्टेट के तत्कालीन हाईकोर्ट ने इन संपत्तियों को गलत पीठ का माना था। उन्होंने आगे कहा कि अपीलार्थी के पिता को मेरिट के आधार पर तत्कालीन जयपुर स्टेट ने नियुक्त किया था और अपीलार्थी को महंत के रूप में नियुक्ति कभी हुई ही नहीं थी। माथुर ने अदालत को कहा कि अपीलार्थी ने उत्तराधिकार

के आधार पर स्वयं को महंत घोषित कर दिया, इसके अलावा अपीलार्थी ने गलत पीठ की कई संपत्तियों को खुर्द-बुर्द भी किया है। करीब दो घंटे से ज्यादा सुनवाई होने के बाद करीब 4.30 बजे अदालत के उठने का समय आ गया था, तब याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उन्हें सुचना मिली है कि अधिकारी मौके पर पहुंचकर अवधेशाचार्य के घर का ताला तोड़ रहे हैं और मठ के आसपास की दुकानों पर भी कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अदालत को इस अपील की पूर्ण सुनवाई करनी होगी तथा तब तक यथा स्थिति बनाई रखी जाये जिस पर अदालत ने यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश दिये और मामले में सरकार की तरफ से इतनी त्वरित कार्यवाही करने पर भी नाराजगी जताई। स्वामी अवधेशाचार्य के वकीलों ने बताया कि अदालत का फैसला उनके तत्कालीन अवधेशाचार्य व उनका परिवार ही पीठ में पूजा अर्चना जारी रखेगा।

### भारतवासी 58 देशों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) किया जाता है। इसके विपरीत 2024 में, भारत 82वें स्थान पर है और 58 देशों की वीजा प्री यात्रा करवा रहा है, जिसमें इण्डोनेशिया, मालदीव और थाइलैण्ड जैसे लोकप्रिय पर्यटक देश शामिल हैं। भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। वर्ष 2023 में 84वें और वर्ष 2022 में 83वें स्थान पर था।

भारत के नागरिक अब अंगोला, बारबडोस, भूटान, बोलीविया, ब्रिटीश, वर्जिन आइलैंड्स, बुरुण्डी, कम्बोडिया, केप वर्ड आइलैंड्स, कमास आइलैंड्स, कुक आइलैंड्स, जिब्राल्टी, डोमिनिका, इथोपिया, फिजी, ग्रेनडा, गुयाना, बिसाऊ, हैती, इन्डोनेशिया, ईरान, जमैका, जॉर्डन, कजाखस्तान, केन्या, किरिबाती,

लाओस, मकाओ (एस.ए.आर. चीन), मैडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मार्शल आइलैंड्स, मॉरीशस, मॉरीशस, माइक्रोनेशिया, मांटसरा, मोजम्बीक, म्यांमार, नेपाल, नू, पलाउ आइलैंड्स, कतर, रवांडा, सभोआ, सेनेगल, सेशल्स, सिएरा लियोन, सोमालिया, श्रीलंका, सेंट कित्स एवं नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विन्सेंट एवं ग्रेनेडाइन्स, तंजानिया, थाइलैण्ड, तिमोर लैस्त, ट्रिनिडाड एवं टोबेगो, ट्यूनिशिया, तुवालु, वनुआतु और जिम्बाब्वे की वीजा प्री यात्रा कर सकते हैं। पाकिस्तान के कमजोर पासपोर्ट की रैंक यमन के बराबर है और वह पिछले वर्ष की तरह इस बार भी इराक (101), सीरिया (102) और अफगानिस्तान (103) से आगे है।

## मोची की गुमटी में बैठ चप्पल की सिलाई की राहुल गांधी ने

सुलतानपुर, 26 जुलाई (वार्ता) कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज सुलतानपुर न्यायालय में पेशी से वापस होते समय एक मोची की दुकान पर रुके और अपने चर्चित अंदाज में जूते और चप्पलों में टांके लगाए और उसका कुशलक्षेम पूछा। मोची ने कोल्ड ड्रिंक पिलाकर नेता विपक्ष का स्वागत किया।

गांधी आज सुलतानपुर में मानहानि के एक मामले में अपना बयान दर्ज करवाने पहुंचे हुए थे। कोर्ट की कार्यवाही पूरी करने के बाद राहुल पुनः पूर्वांचल

सुलतानपुर कोर्ट में पेशी से वापस लौटते हुये एक बार फिर अपने चर्चित अंदाज में दिखे राहुल गांधी।

एक्सप्रेस वे के रास्ते लखनऊ के लिए रवाना हुए थे। पहले अयोध्या प्रयागराज हाइवे पर कूरेभार थानाक्षेत्र के विधायक नगर चौराहे के पास अचानक से उनका काफिला रुका और वे गाड़ी से उतरकर रामचेत मोची की गुमटी वाली दुकान पर

## राज्य सरकार प्रदेश में एम.एस.पी. पर बाजरे की खरीद पर विचार करेगी

विधानसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आश्वासन दिया

जयपुर, 26 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) पर बाजरे की खरीद पर विचार करेगी। उन्होंने शुक्रवार को विधानसभा में प्रखानिक के दौरान बाजरे की खरीद पर पूछे गए प्रश्न पर स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को पत्र लिखा है।

मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के पांच साल के कार्यकाल में प्रदेश के किसानों के साथ धोखा हुआ और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरे की फसल की खरीद नहीं की गई। उन्होंने कहा कि गत सरकार के समय में बाजरे के किसानों को 1400 रुपए से 1500 रुपए प्रति क्विंटल की

विधानसभा के प्रश्नकाल में बाजरे की खरीद पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि गत सरकार के समय में किसानों को 1400 से 1500 रुपए प्रति क्विंटल पर बाजरा बेचना पड़ रहा था, जबकि, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा व मध्य प्रदेश में बाजरा 2300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बिक रहा था।

मुख्यमंत्री ने कहा हमारी सरकार किसानों को लाभान्वित करने की पूरी कोशिश करेगी।

दर पर अपनी फसल बेचने को मजबूर होना पड़ा, जबकि उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश के किसानों का बाजरा 2300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बिक रहा था।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जो कहती है, वह करके दिखाती है। वर्तमान सरकार के गठन के बाद बाजरे

की पहली फसल आएगी। हम किसानों को लाभान्वित करने का पूरा प्रयास करेंगे।

इससे पहले खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बाजरे के उत्पादन और खरीद के सम्बन्ध में सदस्य डॉ. ऋतु बनावत द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि

### राहुल गांधी को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रसंगवश बता दें कि प्रियंका गांधी का लोदी ऐस्टेट स्थित बैंगला भी उस समय खाली पर दिया गया था, जब सरकार ने गांधी परिवार को सुरक्षा की दृष्टि से दी गई एस.पी.जी. सुरक्षा हटा दी गई थी तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सी.आर.पी.एफ. को दे दी गई थी। उस समय से वे प्राइवेट आवास में रह रही हैं। लेकिन जब वे केरल की वायनाड सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, जो राहुल गांधी ने खाली कर दी है तथा अगर वे जीत जाती हैं, जिसकी काफी संभावना है तो उन्हें भी एक सरकारी बैंगला आवंटित हो जायेगा।

सुरक्षा कार्यों से बनाई गई गार्डरैलियों के अनुसार, बैंगला दो तरफ से खुला होना चाहिये तथा दोनों तरफ दो-दो दरवाजे होने चाहिये। इस प्रकार आने वाले दिनों में गांधी परिवार के तीनों व्यक्ति अपने-अपने घरों में पहुँच जायेंगे।

## रोज 14 घंटे काम करने का प्रस्ताव...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आसान बना देगी। यह संशोधन कम्पनियों को यह अनुमति दे देगा कि वे मौजूदा तीन शिफ्ट वाली व्यवस्था के स्थान पर दो शिफ्ट वाली व्यवस्था ला सकें तथा एक-तिहाई श्रमिकों से उनकी नौकरी छीन ली जायेगी।

प्रस्तावित “कनॉटक शॉप एंड कॉमर्सियल ऐस्टाब्लिशमेंट्स (अमेन्डमेंट) बिल 2024” वर्तमान अधिनियम, जिसमें ओवरटाइम सहित एक दिन में अधिकतम 10 घंटे काम लेने की अनुमति दी गई है, के स्थान पर प्रतिदिन 14 घंटे काम करना अनिवार्य कर देगा।

एक दिन में 14 घंटे तक आई.टी. कर्मचारियों के लिए काम के घंटों में वृद्धि करने पर एन.ए.एस.सी. सी.ओ.एम. (नासकोम) ने अपनी रोचक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वे सरकार के इस कदम का समर्थन

नहीं करते हैं।

नैसकॉम के उपाध्यक्ष व लोक नीति के प्रमुख आशीष अग्रवाल ने कहा कि “नासकोम के बतौर हमने एक दिन में 14 काम के घंटों के लिए अनुरोध नहीं किया है या एक सप्ताह में 70 घंटे काम का भी नहीं किया। हमने कनॉटक में इस विधेयक की प्रति नहीं देखी है इसलिए इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

हम पूर्ण रूप से एक सप्ताह में 48 घंटे काम का समर्थन करते हैं जो कि पूरे देश में एक मानक है।

उन्होंने एक बयान में आगे कहा कि “हमने राज्यों व केन्द्र सरकार से जो कहा था, वह यह है कि 48 घंटों का कार्यसिमा को कुछ लचीला बनाने पर विचार किया जाए ऐसा करने से कंपनियों को अखिल भारतीय स्तर पर अपना मानक कार्य संभालाने में मदद मिलेगी। कनॉटक में कुछ माह पूर्व

हमने इस तरह का विचार-विमर्श आई.टी. विभाग के साथ किया था। हालांकि, हमारी इस विषय पर श्रम विभाग के साथ कोई बैठक नहीं हुई थी।”

कनॉटक के चैम्बर ऑफ कामर्स व उद्योग ने भी कहा कि आई.टी. सेक्टर में लगभग आधे कर्मचारीगण पहले से ही मानसिक स्वास्थ्य के मामलों, जैसे कि अवसाद के रोग व शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों से जूझ रहे हैं।

के.सी.सी.आई. ने कहा कि काम के घंटों में बढ़ोतरी करने से स्थिति और भी खराब हो जाएगी, उन्होंने डब्ल्यू.एच.ओ. आई.एल.ओ. के एक अध्ययन का उल्लेख करते हुए कहा कि काम के घंटों में वृद्धि करने के कारण, अनुमान अनुसार, स्ट्रोक से मृत्यु होने का खतरा 35 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा तथा हृदय रोग से मृत्यु का खतरा 17 प्रतिशत ज्यादा बढ़ जाएगा।

## शांति धारीवाल ने विधानसभा में अपशब्द कहे

सभापति संदीप शर्मा के टोकने पर धारीवाल बोले “कोटा में रहना है कि नहीं”

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर, 26 जुलाई। राजस्थान विधानसभा में नगरीय विकास विभाग की अनुदान मांगों पर बहस करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व यू.डी.एच. मंत्री शांति धारीवाल ने अपशब्द बोले। यह मामला देर रात तक सदन में गर्मागर्मा खूद स्पीकर वासुदेव देवनाजी ने कहा कि “यह निंदनीय और शर्मनाक बात है कि पूर्व मंत्री के मुंह से मां-बहन की गाली जैसे शब्द निकले।” इस पर पूरा वीडियो देखकर सोमवार को अपना निर्णय दूंगा।”

दरअसल धारीवाल ने चर्चा के दौरान, पहली बार कांग्रेस राज के दौरान गडबड़ियों पर लगे आरोपों पर पलटवार करते हुए अपशब्द का इस्तेमाल किया। दूसरी बार उन्होंने फर्जी पट्टे जारी करने के मामले में तथा तीसरी बार सभापति

पूर्व मंत्री श्रीचंद कूपलानी ने जब धारीवाल के शब्दों पर आपत्ति जताई तो धारीवाल ने कहा, “कूपलानी जी! आप तो मेरे मित्र हो, एक बार गाली से मंत्री बन गए थे, आप जानकारी हासिल नहीं कर पाए थे। अब मैं जो बोल रहा हूँ, अपना ज्ञान बढ़ाओ।”

स्पीकर देवनाजी ने सारे प्रकरण पर कहा कि, “पूर्व मंत्री के मुंह से गाली जैसे शब्द निकलना निंदनीय है। मैं पूरा वीडियो देखकर सोमवार को निर्णय दूंगा।”

संदीप शर्मा के टोकने पर अपशब्दों का इस्तेमाल कर दिया।

जब सभापति संदीप शर्मा ने शांति धारीवाल को अपनी बात खत्म करने को कहा तो धारीवाल ने अपशब्द के साथ सभापति को यहां तक कह दिया, “तुम तो कोटा के हो, कोटा में रहना है कि नहीं

बार गलती से मंत्री बन गए थे, आप जानकारी हासिल नहीं कर पाए थे। अब मैं जो बोल रहा हूँ, अपना ज्ञान बढ़ाओ।” इससे पहले जब मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने पिछली कांग्रेस सरकार पर फर्जी पट्टे देने का आरोप लगाया तो धारीवाल ने कहा, “नगर निकायों में इस तरह का स्टाफ बैठता हुआ है, लेकिन इसकी वजह से पट्टे बांटना बंद थोड़े ही कर देंगे। शिकायत आती है तो जांच होती है, जांच करते हैं। आप भी जांच करावाइए, सर्वेस्ट ऑफिस, बर्खास्त कीजिए। धारीवाल ने दावा कि पिछली सरकार में उन्होंने 13 लाख पट्टे बांटे, लेकिन सिर्फ 254 पट्टों में ही गडबड़ियां मिली हैं।

इससे पहले धारीवाल ने नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खरार पर

टिप्पणी करते हुए कहा, “पिछले 7 माह से नगरीय निकायों में काम बंद पड़ा है। आपके कार्यों पर क्या क्रियायें निकालें, पिछले 7 माह में कुछ किया ही नहीं। उन्होंने यह चुटकी इस्तेमाल ली, क्योंकि मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने सदन में कहा था कि, पिछली कांग्रेस सरकार में नगरीय निकायों में कई गडबड़ियां की थीं, लेकिन इस सरकार पर कोई एक पैसा का भी आरोप नहीं लगा सकता। गर्ग की इस बात पर चुटकी लेते हुए धारीवाल ने कहा कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के 7 माह बाद भी नगरीय विकास विभाग में काम ठप पड़ा है, मंत्रीजी सभी निकायों व विकास प्राधिकरणों की शक्तियां छीनकर खुद के नियंत्रण में लेने में लगे हुए हैं।” कब्जे में करने में लगे हैं।

### प्रियंका ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जवाब दें, इसे रोकने की पहल करें। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अमेरिकी संसद में संबोधन के बाद प्रियंका ने इजराइल सरकार को बर्बर कारा प्रियंका का यह कोटेशन को अस्वीकार कर दिया। प्रियंका का ध्यान खींचना जो इजराइल के हमले पर मौन साधे है। मोदी सरकार की इजराइल समर्थक नीति से पश्चिम एशियाई देश भली-भांति वाकिफ हैं।

प्रियंका ने कहा कि नेतन्याहू को अमेरिकी संसद को संबोधित करते देखना बेहद शर्मनाक है।

### ‘एल.पी.जी. बाटलिंग प्लांट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव व जस्टिस आशुतोष कुमार की ‘खंडपीठ ने यह आदेश ओमप्रकाश टांक की जनहित याचिका पर दिए अदालत में सांगनेर पुलिस को भी निर्देश दिए हैं कि आई.ओ.सी.एल. परिसर के बाहर गैस के टैंकर व सिलेंडर भरे वाहनों की अवैध तौर पर पार्किंग नहीं होने दें।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डॉ. अभिनव शर्मा ने कहा कि साल 2009 में आई.ओ.सी.एल. के पशुल ऑयल स्टोरेज प्लांट में लगी आग में 12 लोगों की मौत हुई थी। डिपो की आग एक हफ्ते धधकती रही और प्रशासन देखा रहा, लेकिन इस हादसे के बाद भी कोई सुरक्षात्मक कदम नहीं उठाए गए जबकि, राज्य सरकार की जांच कमेटी ने 2011

की रिपोर्ट में माना था कि आई.ओ.सी.एल. के सीतापुरा स्थित घरेलू गैस के बाटलिंग प्लांट को जातपुरा व सीतापुरा में आबादी विस्तार को देखते हुए शहर से बाहर भेजना चाहिए। जनहित याचिका में कहा गया है कि 1996 में यहां पर आबादी नहीं थी और इसलिए ही जयपुर से 30 किमी दूर इस जगह पर बाटलिंग प्लांट बना। इस प्लांट में जमानर लुग्गी गैस पाइप लाइन से एल.पी.जी. उच्च दबाव पर सप्लाई होती है। इसके ऊपर ही महात्मा गांधी अस्पताल के बारे में कहा जाता है कि उसने इस आदेश का उल्लंघन करने वाले पर पहली बार अपराध करने पर 2000 रुपए का जुर्माना व दूसरी बार इसी तरह आदेश की अवहेलना करते पाए जाने पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया।

आलोचना की है तथा इसे मुस्लिमों के साथ भेदभाव करने वाला बताया है। मध्य प्रदेश में भी भाजपा शासित उज्जैन महानगर पालिका ने ऐसा ही एक स्कुलर जारी किया है जिसमें शहर में दुम्कानों के मालिकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी दुम्कानों व संस्थानों के बाहर अपना नाम व मोबाइल नम्बर प्रदर्शित करें। उज्जैन महानगर पालिका के बारे में कहा जाता है कि उसने इस आदेश का उल्लंघन करने वाले पर पहली बार अपराध करने पर 2000 रुपए का जुर्माना व दूसरी बार इसी तरह आदेश की अवहेलना करते पाए जाने पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया।

बैंच ने आज उज्जैन महानगर पालिका से अपना पक्ष रखने को कहा। मुस्लिम संगठनों ने इस फैसले की कटु आलोचना की है तथा इसे मुस्लिमों के साथ भेदभाव करने वाला बताया है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध हैं तथा पहचान करके उनको अलग-थलग करने का उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा, यह निर्णय कानून व व्यवस्था के हित में है। यूपी सरकार ने 19 जुलाई को यह आदेश जारी किया है और कांवेड यात्रा के मार्ग में स्थित सभी भोजन व पेय पदार्थ विक्रेताओं को इसका पालन करना है और इनको संचालित करने वाले संस्थानों के मालिक अपनी दुकान व संस्थान के बाहर पहचान के लिए अपना नाम प्रदर्शित करेंगे। हालांकि, विपक्षी राजनीतिक दलों एवं मुस्लिम संगठनों ने इस फैसले की कटु